वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खुद भारत सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही महोदया, पिछले वर्ष के जुलाई महीने में भारत सरकार तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच में एक बैठक हुई थी और बैठक करके एक समझौते पर सहमति हुई अमल किया गया था। लेकिन महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि वह समझौता हो गया लेकिन आज तक उस समझौते पर अमल नहीं हो पा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदया, हाल ही में जूट उद्योग की ओर से केन्द्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में तमाम मालिकों को तो शामिल किया गया है लेकिन मजदूर संगठनों के एक भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि तमाम मजदूर संगठनों ने कहा कि हम एक ऐसी कमेटी के सामने अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे जिस कमेटी में मजदूरों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो महोदया, आज हालत क्या है? आज जूट के व्यापार पर सटोरियों का कब्जा हो गया है। सटोरिए कृत्रिम रूप से पाट की कमी बाजार में करने का बहाना करके अनाप-शनाप मुनाफा लूट रहे हैं। जूट कमिश्नर आफ इंडिया के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वह आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष हमारे देश में 95 लाख टन गांठों का भंडार का उत्पादन हुआ है जो कि हमारे देश की उत्पादन क्षमता के बिल्कुल अनुरूप है। लेकिन इसके बावजूद बाजार में यह स्थिति पैदा कर दी गई कि बाजार में गांठों का अभाव हो गया और इसके चलते मिलों तक को माल नहीं मिल पाया और मिलें बंद कर दी गईं और मजदूरों की छंटाई कर दी गई। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारा जो जूट उद्योग है इतने भयंकर संकट से गुजर रहा है जो कि हमारे देश का परम्परागत उद्योग है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है कि जिसके बारे में खुद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जे०सी०आई० की इसकी इजारेदार होनी चाहिए, पार्ट की खरीदारी में जे०टी०आई० की इजारेदारी होनी चाहिए लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार निर्णय लेती है लेकिन किसी भी एक निर्णय पर अमल नहीं होता। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहलवाना चाहूंगी कि जो तीन लाख मजदूर और दस लाख किसानों के परिवारों की जिंदगी आज संकट में पड़ी हुई है, तो भारत सरकार तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे, ताकि यह हड़ताल पुरानी हड़तालों की तरह 50-50 दिन तक न खिंचे और मजदूर भूल की जिंदगी जीने को विवश न हो। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would like to point out to Members.....

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Madam, I only want to associate myself with the Special Mention made by Shrimati Sarala Maheshwari. I am not making any speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please. I have nine names before me. We have fifteen minutes left. You can divide the time amongst yourselves accordingly. I have no objection.

SHRI JIBON ROY: I am simply associating with it, Madam. I am not speaking.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Biplab Dasgupta has given his name. There are ten names, you can divide the time amongst yourselves and take a minute or two each. I do not want the Members whose names are listed later to suffer. Please abide by the time-limit in your own interest. I have no problem. Shri Chaturanan Mishra, please.

Need to reveal names of Ministers and MPs mentioned in the diary of Shri S.K. Jain is Hawala Case

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिए हवाला कांड की चर्चा करना चाहता हूं। हम लोग आम चुनाव में जा रहे हैं और हमारे देश के उच्चकोटि के नेता काले बादल से घिरे हुए हैं। यह उचित नहीं है कि पार्लियामेंट को इससे वंचित रखा जाए और सरकार पब्लिक को भी इससे वंचित रखे। इसमें बड़े चोटी के नेता लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप उस पर एतराज करेंगी। लेकिन अखबारों को आजादी है और उन्होंने सब का नाम छाप दिया है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो यह भारी भ्रष्टाचार का मामला है इस पर हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जो उससे भी ज्यादा चिंता की बात आई है वह यह है कि सरकार ने उन आफिसरों का जो इसकी जांच कर रहे थे, उनको सरकार ने वहां से हटा दिया है। अखबार में जो आया है उसको मैं पढ़ता हूं:

"Mr. B.R. Lal, a Joint Director in the Central Bureau of Investigation, who had been handling the Rs. 65-crore sensational hawala case involving 115 politicians and bureaucrats has been divested of his responsibility."

इसी तरह से आया है कि:

"Mr. Amod Kant, a DIG rank officer, was shunted out of the CBI."

अगर सरकार ऐसा करती है तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। भ्रष्टाचार का जब मामला आता है, आम भ्रष्टाचार का तो पूरा हाउस उठता है। लेकिन जब अपने अपने नेताओं के बारे में आता है तो कोई नहीं उठता है। मैं तो माथुर जी से भी अनुरोध करूंगा-वे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जोरदार बोलते हैं लेकिन हवाला कांड पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें उनके नेता का नाम है। ऐसे में तो हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि बिना पार्टी के लोगों का ख्याल किए हुए, जैसा यह दुनिया में हो रहा है, अभी साउथ कोरिया में आपने देखा होगा कि उस मुल्क के प्रेसीडेंट पर मुकदमा चला, अरेस्ट हुआ, जापान में हुआ, इससे पहले इटली में हुआ है। हर जगह अगर यही बात है तो हम लोगों को भी इसको करना चाहिए। यदि हमारे नेता क्लंकित रहें, तमाम लोग इसकी चर्चा करें बाजार में कि 10-10 कैबिनेट के मेम्बर इन्वाल्व हैं, तो इसकी सफाई आनी चाहिए। इस बात पर मैं यह नहीं कहता—मामला सब-जूडिश है, इतना ही कहिए कि परिस्थिति क्या है, किस हालत में ये नेता क्लंकित हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम एक नेता हैं हमारे देश में, शरद यादव जिन्होंने कहा कि रुपया कैसे आया और अखबारों में उसकी रिपोर्ट आयी है। बाकी सभी लोग चुप हैं। मौसम स्वीकृति लक्षणम्, अगर इसको मान लिया जाए तो यह सब के सब स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह काम किया है। इसकी सफाई आनी चाहिए और कोई एसपर्शन उन के ऊपर न आए इसके लिए सफाई आनी चाहिए। इसलिए जिन कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम है उन्हें यहां सदन में आकर देश को जानकारी देनी चाहिए कि क्या बात हुई कि असलियत क्या है। इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश): मिश्रा जी ने जो कहा है मैं अपने को उससे ऐसोसियेट करता हूं।

मौलाना عبید اللہ خاں اعظمی: مشرا جی نے جو کہا ہے میں اپنے کو اس سے ایسوسیٹ کرتا ہوں۔

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam....*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to associate? Mrs. Alva wants to reply. Just associate--don't make a speech.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Just two minutes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can't give two minutes,

DR. BIPLAB DASGUPTA: One minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am so sorry, because there are other Members. Now, Members should not get angry with me if their time is curtailed. If Mrs. Sushma Swaraj does not get her chance, I am not responsible! Mrs. Alva wants to reply to it....*(Interruptions)*.. Just say that you associate yourself.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, while saying that this motion moved by Mr. Chaturanan Mishra....

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a motion; it is a special Mention.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I recall that in the last session we discussed the Vohra Committee report and the web of corruption in which politicians and criminals are enmeshed. Now there is tangible proof that some of our politicians, very prominent members, are on the pay roll of crooks. It has been known, earlier also, that there are many politicians in our country who live beyond their means and the style in which they live cannot be justified either by inheritance or in terms of the salaries they receive. So, now there is need for a public examination in this particular case: I thoroughly agree with Chaturananji. There are many names which have been mentioned here, and it is not enough to say that the case is in the court. As public figures, they should come out with their own statements as to why their names are figuring in the list of crooks.

Thank you very much, Madam.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, two issues are involved--I am not going into the details. First of all, about the statement that 10

Cabinet Ministers' names are there or something. There are names across the board: I am not naming anybody. These are known, published. So I am not going into that.

The second point that has been made is that these people should come to the House--all the leaders whose names have been mentioned-- and make a statement in the House. I would only say that this is a public interest litigation in the Supreme Court and it is, therefore, sub judice. It is being heard partly in camera, even in the Supreme Court, by a very senior Bench and, therefore, I am not commenting on what is happening in the court.

But I would like to answer one point which the hon. Member has made, that we have shunted out officers who were investigating this matter. I am not holding a brief for anybody. I can only say that there are certain deputation rules and certain seniority rules by which postings and transfers are made.

In this case, the same charge was made before the Supreme Court in a public interest petition that we were shunting them out. The Supreme Court called for the filing of affidavit and after looking into it passed orders saying very clearly that there was no reason to stay these transfers. The order of the Supreme Court is very clear that there has been no out-of-the-way moving of any officer in the case. I am just clarifying the position.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) मैंने यह कह दिया था कि जो सब-जुडिस है..*(व्यवधान)* उसकी बात नहीं है।

उपसभापतिः इस मामले पर बहस नहीं होगी।

श्री चतुरानन मिश्रः हमने यह कह दिया था कि जो सब-जुडिस है *(व्यवधान)* उसकी बात नहीं है।

+[مشتری محمد سلیم : منتری مہودے کیا
آکر بتائیں ۔۔۔ "مداخلت" ۔۔۔]

श्री चतुरानन मिश्रः हमने यह कह दिया था कि जो सब-जुडिस है वह हम नहीं चाहते हैं लेकिन मंत्री महोदय को यहां पर आ कर कहने में क्या एतराज है कि उन्होंने रुपया नहीं लिया *(व्यवधान)* अगर नहीं लिया है तो कहें यह तो सब-जुडिस नहीं है *(व्यवधान)*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): No, no.

SHRI CHATURANAN MISHRA: How can it be? We cannot have such Ministers. There are charges against them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, let us not argue about this. ...*(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: I tell you that then it is not parliamentary democracy to continue ministers with such charges. It is not in the interest of parliamentary democracy. They can defend their case. ...*(Interruptions)* If they are not involved.

SHRI V. NARAYANASAMY: Where is the authentic proof? They are only allegations. ...*(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: I have clearly said that. ...*(Interruptions)*

Mr. Narayanasamy, this is not fair on your part.

SHRI V. NARAYANASAMY: The matter is pending in the court. ...*(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am not saying that. We want our Ministers and Members of Parliament to come and speak the truth. I do not want to go into the case. ...*(Interruptions)*

No, no, that is not the case. ..*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: The Government has co-operated. The investigation is going on. The Judges are looking into the matter. What more do you want? ...(Interruptions)

DR. BIPLAB DASGUPTA: The BJP Members have nothing to say on this. Their members also have been implicated in this.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ

(Haryana): Mr. J.P. Mathur stood up and associated himself with Mr. Chaturanan Mishra.

DR. BIPLAB DASGUPTA: What about politicians?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Even politicians. Yes, we want it. ...*(Interruptions)*

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: हाऊस में अगर इलज़ाम लगा है तो वह जवाब देंगे या नहीं देंगे? **(व्यवधान)**

*Hمولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب
میں اگر الزام لگایا ہے تو وہ جواب دینگے
یا نہیں دینگے - ۰۰۰ ہزار ذات ۰۰۰ م

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I do not know how the issue had been allowed to be raised in the House.

श्रीमती सुषमा स्वराज: जांच होनी चाहिये कि किस ने पैसा लिया है **(व्यवधान)** हमने कब मना किया है कि इस बात से **(व्यवधान)** सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है **(व्यवधान)**

उपसभापति: अभी बैठ जाइये **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र: कौन रोकता है **(व्यवधान)** पा०ज०पा० के जिन मैम्बरों पर चार्ज है वह आगे क्यों नहीं आते हैं **(व्यवधान)** कौन रोकता है? उनको यहां आना चाहिये **(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY: They cannot respond. Madam, there is no charge. The Government is co-operating.

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमारे यहां किसी को भी एतराज नहीं है **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र: यह अपने अपने हाऊस में बोलें कि क्या चार्ज है. **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं **(व्यवधान)**

उपसभापति: अभी आप बैठ जाइये प्लीज़। **(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY: The names of politicians and others are there in the newspapers. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salim, please sit down.

Mr. Narayanasamy, please sit down. ...*(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: They are criminalising politics.

They are taking money from them. ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, there are 2,000 custodial deaths every year in West Bengal. He is talking about criminalisation of politics. ...*(Interruptions)*

Two thousand persons died in custody in one year in West Bengal. There are no human rights there. ...*(Interruptions)*

श्री चतुरानन मिश्र: हमें एक मिनट टाइम दे दीजिए।

उपसभापति : जब मैं खड़ी हूं तब आप बैठ जाइए।

श्री चतुरानन मिश्र: हम बैठ जाते हैं। आपके हुक्म को मान रहे हैं। केवल आधा मिनट दे दीजिए।

उपसभापति: मेरा हुक्म मान लीजिए...**(व्यवधान)** मिस्टर सलीम प्लीज सिट डाउन। बैठिए...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र: गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव करे कि इलेक्शन के पहले इसको डिसपोज आफ किया जाए। गवर्नमेंट आफ इंडिया मूव करे तब हम समझें कि गवर्नमेंट आनेस्ट है।

I demand only this much that the Government should move the Supreme Court praying that this case should be disposed of before the elections. This is my request. It is not that since the matter is *sub judice* I cannot make this request.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You talked of Bofors in the last elections. What did you get? You blamed late Shri Rajiv Gandi then...*(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am asking you, if you are honest, move the court that it should be disposed of

*[]Transliteration in Arabic Seript.

before the elections. That is all. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I do not know how this is being allowed to be raised, when the matter is pending before the Court.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am not raising the matter. I am only asking her to move in the Supreme Court to dispose of the case before the elections.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the Government has been giving all assistance. *(Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Cabinet Ministers are involved. That is why I am asking this much. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record now. Please sit down. I am not allowing this because you cannot take names of persons who are not here and who cannot defend themselves.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I have not said any name.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have heard one name. Mr. Salim mentioned one name. We should not talk about people who are not present here in the House and who cannot defend themselves. Making allegations is one thing. She has replied as she could reply. She said that the matter is pending in the court. But, just getting up in the House and throwing mud at each other is not going to lead us anywhere.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Let them say that they have not taken money.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Biplab Dasgupta, she has mentioned the whole thing peacefully and he has also mentioned about it. This is the forum and this is your right to mention. But, Mrs. Alva has said that the matter is before the Court and let the court decide it. If the matter had not gone to the court, the House would have decided. The matter is there now. If you suggest that somebody should come and say, it is your viewpoint. Now, let me go ahead, because only three minutes are left before we adjourn for lunch. In am only bothered about the House. *(Interruptions)* There has been misappropriation of the time. Against whose quota should I put it?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, it is not that since the matter is *sub judice*, we cannot ask for moving the court to have it disposed of before the elections.

उपसभापति : चतुरानन जी इस हाउस का समय जो नष्ट होता है, जो दूसरे लोग ले लेते हैं इनका हिस्सा बीसीजी के हिस्से का समय था आपने ले लिया, दूसरों ने ले लिया। अब मैं किसको दोषी ठहराऊं।

श्री चतुरानन मिश्र: सबका हिस्सा तो उन लोगों ने ले लिया, सारे देश का हिस्सा ले लिया....

उपसभापति : आपने तो उन सबका हिस्सा ले लिया।

श्री चतुरानन मिश्र: आप टाइम का हिस्सा कह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि पब्लिक का हिस्सा रुपया ले लिया उन्होंने।

उपसभापति : आपने तो सनातन बीसीजी का हिस्सा ले लिया। वे बेचारे इतनी देर से खड़े हैं। वे थक गए होंगे खड़े-खड़े।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: हिस्सा ले लें, कमीशन न लें

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: حصہ لے لیں۔ کمیشن نہ لیں۔[*]

Demand for Autonomous development Council for Western Orissa

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Madam, in the year 1969, the National Council for Applied Economic Research had made a survey of the backward and Western districts of Orissa and had remarked "Socially and economically, the Western region of Orissa, constitutes the most backward part of the State. Such backwardness is characterised by low income levels, higher dependence of population on poorly developed

*[ ]Transliteration in Arabic script.